



■ भारत-यूरोपीय संघ का ध्यान अब एफटीए रक्षा सौदे पर : फ्रॉन डेर लायन-12



■ शेयर बाजार में गिरावट यमी सेसेव्स 939 अंक चढ़ा, निपटी 23,400 के पार-12



■ राज्यसभा में एलापीजी को लेकर हंगामा खरगे बोले सरकार दोषी-13



■ भारतीय खिलाड़ी सूर्यकुमार बोले- टेस्ट खेलना चाहंगा लेकिन हाथ सेट है टी20 में-14

आज का मौसम **32.0°**
अधिकतम तापमान
18.0°
न्यूनतम तापमान
सूर्योदय 06.21
सूर्यास्त 06.21

आमृत विचार

एक संपूर्ण दैनिक अखबार

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर
मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

www.amritvichar.com

मंगलवार, 17 मार्च 2026, वर्ष 7, अंक 111, पृष्ठ 14 मूल्य 6 रुपये

चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उपरांत 09:23 चतुर्दशी विक्रम संवत् 2083

गरीब को बिना आवास नहीं रहने देंगे : योगी

मुख्यमंत्री ने शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों को 900 करोड़ की पहली किस्त जारी की

प्रधानमंत्री आवास योजना

● योगी ने कहा- लक्ष्य केवल मकान देना नहीं, बल्कि गरीबों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है मकसद



लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट दबाकर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए किस्त जारी करते सीएम योगी (साथ में मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी)।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 90 हजार लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी गरीब को बिना आवास के नहीं रहने दिया जाएगा। जिन माफियाओं ने वर्षों तक गरीबों का हक छीना और जमीनों पर कब्जा किया, अब उन्हीं जमीनों को मुक्त करकर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल मकान देना नहीं, बल्कि गरीबों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में

आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों में संवाद करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को परिवार मानकर बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 62 लाख परिवारों को आवास मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले योजनाएं होने के बावजूद गरीबों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब पारदर्शी

माफिया से मुक्त जमीनों पर बनाए जाएंगे आवास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग गरीबों के लिए आवास निर्माण में किया जाए। जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए इन जमीनों पर हाईराइज आवासीय परियोजनाएं विकसित की जाएं। साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 75 प्रतिशत कार्य पूरा होते ही लाभार्थियों को दूसरी किस्त भी समय से उपलब्ध कराई जाए।

योजना के साथ लाभार्थियों को राशन, उच्चल्ला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इससे गरीबों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो रहा है और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

ओडिशा में अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग, 10 मरीजों की मौत

भुवनेश्वर, एजेंसी

ओडिशा सरकार द्वारा कटक में संचालित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आईसीयू में रविवार देर रात भीषण आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के दौरान अस्पताल के करीब 11 कर्मचारी झुलस गए। मुख्यमंत्री ने छह सदस्यों की एक जांच टीम बनाई है, जो आग लगने की वजह की जांच करेगी और आज शाम तक अपनी रिपोर्ट देगी।



एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आईसीयू में जला पड़ा सामान।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, विकास आयुक्त डीके सिंह की अगुवाई में बनी जांच टीम एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जाएगी और आज शाम तक मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माझी ने बताया कि आग शायद शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। एक अधिकारी ने बताया कि आग देर रात ढाई बजे से तीन बजे के बीच लगी और दमकलकर्मी तुरंत अस्पताल पहुंचे व आग बुझाने के लिए अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आग लगने की घटना में मरीजों की मौत

● कटक के श्रीराम चंद्र भांजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगी थी आग, 11 कर्मी झुलसे

● मृतकों के परिजन को 25-25 लाख मुआवजा, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा

आईसीयू और उससे सटे वार्ड में 23 मरीज थे भर्ती

मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि ओर उससे सटे आईसीयू व वार्ड में 23 मरीज भर्ती थे। आग लगने से सात मरीजों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोगों की मौत दम घुटने से हुई। उन्होंने कहा कि अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग के आईसीयू में आग लगी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज किया जा रहा था। माझी ने इस मामले में न्यायिक जांच की भी घोषणा की और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक को मामले की जांच करने तथा तुरंत उन्हें रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।

पर शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 25 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त कर घायलों के स्वस्थ होने की कामना की।

न्यूज ब्रीफ

विश्व बैंक ने उग्र में स्वच्छ वायु के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्ज को मंजूरी दी

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने सोमवार को उत्तर प्रदेश को स्वच्छ वायु बदलाव परियोजना के लिए लगभग 30 करोड़ डॉलर का ऋण देने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कर्ज उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छ वायु योजना को समर्थन देगा। यह राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार और युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एकूतिक समाधान पर केंद्रित है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम (299.66 करोड़ डॉलर) परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ वायु बदलाव पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे स्वच्छ वायु के लाभ अन्य राज्यों तक भी पहुंचेंगे।

ईरान बोला- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला, पर दुश्मनों के लिए बंद

तेहरा/लंदन, एजेंसी



ईरान पर अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले के दो सप्ताह बाद भी सोमवार को दोनों पक्षों में लड़ाई जारी रही। इजराइल ने जहां लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम वर्षा की वहीं, ईरान ने जवाबी हमले के रूप में इजराइल के अलावा पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और तेल अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को कहा कि होर्मुज मार्ग ईरान के दृष्टिकोण से खुला है, लेकिन उन देशों और उनके सहयोगियों के लिए बंद है जिन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवायापूर्ण आक्रामकता की है। अराघची ने कहा कि ईरान अपनी रक्षा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखता और आवश्यकता पड़ने तक युद्ध जारी रखेगा। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि वह ब्रिटेन को प. व्यापक युद्ध में घसीटे जाने की अनुमति नहीं देते। वह यूरोपीय सहयोगियों से मिलकर खाड़ी को खोलने के लिए एक व्यवहार्य योजना तैयार कर रहे हैं।

जंग के बीच पहला भारतीय जहाज एलपीजी लेकर पहुंचा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण ईरान के निकट होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे भारत के 24 जहाजों में से एक एलपीजी टैंकर शिवालिक सोमवार शाम गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया, जबकि दूसरे एलपीजी टैंकर नंदादेवी के मंगलवार सुबह कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। शिवालिक टैंकर पर 45 हजार टन एलपीजी लदी है और इसके आने से देश में एलपीजी की आपूर्ति और मजबूत होगी।

होर्मुज में युद्धपोत तैनात करने वाले ट्रंप के बयान पर भारत का जवाब- अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की गई

नई दिल्ली। भारत ने सोमवार को कहा कि उसने होर्मुज से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के सुरक्षित पारगमन को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जोनाथन ट्रंप द्वारा कई देशों से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को खुला रखने के लिए युद्धपोत भेजने के आह्वान की पुष्टि भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राधाश्री जायसवाल ने कहा, हमें इस बात की जानकारी है कि कई देशों में इस संबंधित मामले पर चर्चा हो रही है। हमने अभी तक द्विपक्षीय स्तर पर इस पर चर्चा नहीं की है। उनकी यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में आई कि क्या अमेरिका ने भारत से इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजने के लिए संपर्क किया था।

भाजपा की बंगाल और केरल के लिए पहली सूची जारी

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। वहीं, केरल में 47 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट कोलकाता के भवानीपुर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। वह नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगे।

नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित, तीन राज्यों में राजग का दबदबा

नई दिल्ली। बिहार के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में 11 सीट पर हुए चुनाव से सतारूद राजग ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्यसभा की कुल 37 रिक्त सीटों में से केवल बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 सीट पर चुनाव हुए, जबकि बाकी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सोमवार रात घोषित परिणामों के अनुसार, राजग ने आठ सीट जीतीं, जिनमें एक उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जबकि बीजद ने एक सीट हासिल की।

सीट के मुताबिक, अनिमा दत्ता को नदिद्या जिले के पलाशीपाड़ा से, जबकि लक्षिकांत साहू को झाड़ग्राम से टिकट दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 2021 में हुए उपचुनाव में भवानीपुर से जीत हासिल की थी। बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका इस सीट से जीतना महत्वपूर्ण था। बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 23 व 29 अप्रैल को मतदान होगा, मतगणना 4 मई को होगी।

रासबिहारी सीट से स्वप्न दासगुप्ता को टिकट दिया गया है। भाजपा ने सुमिता सिन्हा को पूर्व मैदिनीपुर जिले के कांथी उत्तर से, बिमान घोष को हुगली जिले के पुरसुहद से और माधवी महलदर को दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली से मैदान में उतारा है।

लहलुहान होकर भी तेंदुए से लड़ा बहादुर किसान, रस्सी से बांधा

संवाददाता। धौरहरा/ खीरी

अमृत विचार: धौरहरा वन रेंज में मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटना फिर सामने आई है। खेत में घुसे तेंदुए ने हमला किया तो घायल किसान उसे भिड़ गया। देर तक आमने-सामने की भिड़त के बाद किसान ने तेंदुए को काबू कर रस्सी से बांध लिया। तेंदुए के हमले में घायल किसान अंशुल भार्गव (40) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फॉरेस्ट टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर वन रेंज पहुंचा दिया है, जहां परीक्षण के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। ग्राम देवीपुरा



खेत में बंधा पड़ा तेंदुआ।

निवासी अंशुल भार्गव सुबह के समय अपने खेत देखने तो उन्हें गेहूं फसल से जानवर के गुरांने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पास पहुंचे तो तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। घायल होने के बाद भी वह तेंदुए से लड़ते रहे और बांध लिया। पता होते ही तमाम लोग जुट गए और घायल



● खीरी में देवीपुरवा के जंगल में हुई घटना, भटकते हुए खेतों में आ गया था तेंदुआ

अंकुल भार्गव।

किसान को इलाज के लिए भिजवाया। वन क्षेत्राधिकारी नृपेंद्र ने बताया कि तेंदुआ एक साल का है और भटककर गांव की ओर आ गया। वन रेंज में पशु चिकित्सक उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। इस घटना के बाद वन टीमों ने इलाके की निगरानी बढ़ा दी है।

आईएसआईएस से जुड़े होने के आरोप में बीडीएस का छात्र मुरादाबाद से गिरफ्तार

संवाददाता, मुरादाबाद/लखनऊ

अमृत विचार: यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से बीडीएस के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। छात्र पर आतंकी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार छात्र हारिश अली मूलरूप से सहारनपुर का रहने वाला है। एटीएस ने उसके कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ब्रेक करने के लिए वृक्ष का रूप से मुस्लिम युवकों को ब्रेनवॉश कर आर्टिस्ट आईएसएस से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि हारिश अली ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था।



● एटीएस ने की कार्रवाई आरोपी मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है

कई ग्रुप बनाए, करा रहा था युवकों की भर्ती

एटीएस जांच में सामने आया कि हारिश आईएसआईएस माड्यूल के हैंडलरों के सौधे संपर्क में था। उसने इंस्टाग्राम इनक्रिप्टेड एप सेशन व डिसकार्ड पर फर्जी नामों से वटुडू प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से समर्थित ग्रुप बनाए। इन ग्रुप के माध्यम से कट्टरपंथी युवकों को आईएसआईएस में भर्ती किया जा रहा था। हारिश ग्रुपों में आईएसआईएस की मीडिया चैनलों की पत्रिकाओं, प्रचार-प्रसार की सामग्रियों, आतंकी विचारधाराओं व मारे गए आतंकीयों के चित्र, वीडियो व आडियो, आतंकीयों को महिमा मंडित कर साझा किया जाता था।



एक विस्तार रिज दिल्ली में स्थित है और यह एक पथरीला, पहाड़ी और वन क्षेत्र है। प्रशासनिक कारणों से इसे चार क्षेत्रों दक्षिण, दक्षिण-मध्य, मध्य और उत्तर में विभाजित किया गया है जो लगभग 7,784 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। पीठ ने कहा, हमें यह सोच बदलने की

जंगल और हरित क्षेत्रों के प्रबंधन पर गठित समितियों का मांगा विवरण

पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर रिपोर्ट पर यह विवरण पेश करे कि जंगलों और हरित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को देखने के लिए वैधानिक या गैर-वैधानिक समितियों का गठन कैसे किया गया है। न्यायालय ने कहा कि हलफनामा में उन वैधानिक ढांचों पर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए जिनके तहत विभिन्न निकायों का गठन किया गया है। पीठ ने कहा कि हलफनामा दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि विभिन्न समितियां राष्ट्रीय राजधानी और पूरे देश में हरित आवरण के मुद्दे पर गौर कर रही हैं।

जरूरत है कि राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केवल दिल्ली को हरियाली की जरूरत है और बाकी शहरों को नहीं। इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने उच्चतम न्यायालय के 11 नवंबर के फैसले का हवाला दिया, जिसमें केंद्र को दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (डीआरएम्बी) को वैधानिक दर्जा देने और इसे रिज और 'मॉर्फोलॉजिकल रिज' से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल-खिड़की प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया गया था। तब न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत औपचारिक रूप से डीआरएम्बी का गठन करने का निर्देश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान, केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि पिछले साल एक दिसंबर को डीआरएम्बी के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।



न्यूज़ ब्रीफ

‘ग्रेवयार्ड इकॉनमी’ से ‘टैपल इकॉनमी’ की ओर बढ़ रहा यूपी

अमृत विचार, लखनऊ/आगरा : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश अब वर्ष 2017 की ‘ग्रेवयार्ड इकॉनमी’ से निकलकर ‘टैपल इकॉनमी’ की ओर बढ़ रहा है, जहां आस्था, संस्कृति और पर्यटन स्थानीय रोजगार व अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रज रंगोत्सव 2026 के दौरान होली के प्रमुख दिनों में ब्रज क्षेत्र में 44 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को नया बल मिला। संस्कृति मंत्री ने सोमवार को कहा कि मथुरा-वृंदावन से लेकर अयोध्या और वाराणसी तक प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थल वैश्विक पहचान बना रहे हैं।

असम व बंगाल में चुनावी माहौल गरमाएंगे यूपी के कांग्रेस नेता

अमृत विचार, लखनऊ : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी है तो प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। पांचों राज्यों में चुनाव कराने के लिए यूपी से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष दिग्गज कांग्रेस नेताओं को भेजा जाएगा, जोकि राज्यों में जाकर चुनावी माहौल को गरमाएंगे। यूपी से भी दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल और असम समेत पांचों राज्यों में उतारने की योजना तैयार कर ली गई है। इसके लिए करीब 50 नेताओं को चुना जाएगा। इसके लिए गहन मंचन शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पार्टी नेताओं को चुनाव के लिए राज्यों में भेजा जाएगा। इसके लिए नेताओं के कद के हिसाब से लिस्ट तैयार की जा रही है।

1,08,935 गांवों में से 95,765 का भू-संदर्भिकरण पूरा

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश में कृषि क्षेत्र को अधिक पारदर्शी और व्यावस्थित बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। कुल 1,08,935 राजस्व गांवों में से 95,765 गांवों का भू-संदर्भिकरण कार्य पूरा हो चुका है। इसके आधार पर आधार और किसान रबी दोनों मौसम में बढ़े पैमाने पर डिजिटल क्रांप सर्वे किया गया है। खरीफ मौसम में 5.37 करोड़ से अधिक खेतों का सर्वे अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया, जबकि रबी मौसम में भी 5.56 करोड़ से अधिक खेतों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा डिजिटल क्रांप सर्वे और किसान पंजीकरण अभियान के माध्यम से किसानों का सटीक आंकड़ा तैयार करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया गया है।

प्रतियोगिता के आवेदन की अंतिम तिथि 20

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (बीबी-जी राम जी)’ योजना के अंतर्गत लोगो डिजाइन, विजय और रील प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में विजेता को 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च शाम 5:45 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए ‘माय विजिलेंट’ रील/वीडियो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिभागी 30 से 60 सेकंड के वीडियो के माध्यम से अपने गांव की विशेषताओं और विकास की कहानियां साझा करेंगे। ग्राम्य विकास विभाग आयुक्त जी. एस. प्रियदर्शी ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी MyGov या MYBharat पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

मिसाल सब्सिडी से बदली तकदीर, जरबेरा की खेती से लाखों की कमाई

फूलों की खेती से बनाई पहचान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ



बाराबंकी के किसान नीरज पटेल

का निर्णय लिया। उद्यान विभाग के एक कार्यक्रम में उन्हें जरबेरा फूल की खेती के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ इस खेती को अपनाने का फैसला किया। वर्ष 2018 में योजना के तहत उन्हें लगभग 29.50 लाख रुपये का ऋण मिला और बाद में 50 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया गया।

सरकारी सहायता से उन्होंने अपने एक एकड़ खेत में संरक्षित खेती के तहत पॉलीहाउस स्थापित किया। इसमें करीब 25 हजार जरबेरा पौधे लगाए गए हैं, जो एक बार लगाने के बाद लगभग छह वर्ष तक उत्पादन देते हैं। जरबेरा फूलों की मांग शादी, सजावट और विभिन्न आयोजनों में लगातार बनी रहती है। नीरज बताते हैं कि सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें हर साल करीब 8 से 10 लाख रुपये तक की शुद्ध आय हो जाती है। उनकी पहल से आसपास के पांच लोगों को रोजगार भी मिला है। नीरज अब अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले बजट का पूरा उपयोग करें : सचान अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को विभागीय योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट और प्रगति की समीक्षा की। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट व्यय और लंबित परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए सख्त निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले बजट का पूरा उपयोग करें। कैसरबाग स्थित नियात भवन में समीक्षा के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आक्रोश

बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटने पर मुआवजे की मांग

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ



अमृत विचार : प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों में नेगेटिव बैलेंस के चलते लाखों उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए, जिनमें उपभोक्ताओं ने भुगतान करने के बावजूद आरएमएस सिस्टम में रिचार्ज सिंक न होने के कारण समय पर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हो सके। इससे पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं के बीच आक्रोश की स्थिति बन गई।

फिर भी उनके कनेक्शन समय पर नहीं जोड़े गए। परिषद ने मांग की है कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून 2019 के तहत मुआवजा दिया जाए। परिषद ने यह भी मांग उठाई कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जिन उपभोक्ताओं पर बकाया हो गया है, उन्हें पोस्टपेड उपभोक्ता मानते हुए विद्युत वितरण संहिता के तहत किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाए, ताकि गरीब उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। परिषद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिना उपभोक्ताओं को सूचना दिए उनके पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए गए और उन्हें प्रीपेड मीटर में बदल दिया गया, जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन है।

रिचार्ज कराने पर भी प्रदेश के 1.47 लाख घरों में नहीं आई बिजली

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने कारण 2,23,765 विद्युत कनेक्शन आटोमैटिक ढंग से कट गए थे। उनमें से सोमवार तक 76,209 विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं द्वारा रिचार्ज करा लेने के उपरांत पुनः चालू हो गये। लेकिन अभी भी 1,47,556 कनेक्शन कटे हुए हैं, जिससे उनके घरों में अंधेरा है। उधर पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली सप्लाई बंद होने के बाद यदि उपभोक्ता बकाए का 50 फीसदी प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता है तो तो कनेक्शन केवल तीन दिनों के लिए पुनः जोड़ दिया जाएगा।

पावर कारपोरेशन के बहा-कनेक्शन कटने के बाद-बिजली प्रयोग की तो होंगे मुकदमे

सोमवार को पावर कारपोरेशन के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली सप्लाई बंद होने के बाद यदि उपभोक्ता बकाए का 50 फीसदी प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज करता है तो तो कनेक्शन केवल तीन दिनों के लिए पुनः जोड़ दिया जाएगा। प्रवक्ता का कहना है कि यदि इन तीन दिनों के भीतर पूरा बिल नहीं रिचार्ज किया तो दोबारा कनेक्शन कट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटरों के प्रमुख लाभों में सटीक बिलिंग, समय से रिचार्ज और मीटर से छेड़छाड़ नहीं करने पर निर्धारित विद्युत टैरिफ पर दो प्रतिशत छूट दी जा रही है।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार घोषित, 54 कलाकार होंगे सम्मानित

वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक के अकादमी पुरस्कारों के लिए नाम घोषित, संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में योगदान के लिए हुआ चयन

वर्षवार कुल कलाकारों की संख्या

2021 : 12 अकादमी पुरस्कार, 2 विशेष पुरस्कार = 14 कलाकार
2022 : 12 अकादमी पुरस्कार, 2 विशेष पुरस्कार = 14 कलाकार
2023 : 11 अकादमी पुरस्कार, 2 विशेष पुरस्कार = 13 कलाकार
2024 : 11 अकादमी पुरस्कार, 2 विशेष पुरस्कार = 13 कलाकार

जैन के नामों का चयन किया गया है। संगीत नाटक अकादमी की ओर से वर्ष 2023 के लिए शास्त्रीय गायन की श्रेणी में डॉ. रामशंकर, सुगम गायन के लिए मनोज गुप्ता एवं लोक गायन के लिए राकेश श्रीवास्तव को सम्मानित करने की घोषणा की गई। जबकि कथक नृत्य के लिए लखनऊ की डॉ. आकांक्षा श्रीवास्तव, तबला वादन के लिए अनूप बनर्जी और बांसुरी वादन के लिए चेतन कुमार जोशी के नामों का चयन किया गया है। वहीं नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में निर्देशन के लिए राजकुमार उपाध्याय, अभिनय के लिए संजय

देग्लरकर, लेखन-संगीत एवं नृत्य के लिए उमा त्रिगुणायत, कला उन्नयन के लिए डॉ. ओमेन्द्र कुमार एवं कला समीक्षा के लिए अर्जुनदास केसरी को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं सफदर हाशमी पुरस्कार के लिए गजियाबाद के अजय कुमार और बीएम शाह पुरस्कार के लिए गोरखपुर के रविशंकर खरे के नाम का चयन किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2024 के अकादमी पुरस्कार में शास्त्रीय गायन के लिए रीतेश-रजनीश मिश्रा, सुगम गायन के लिए मुक्ता चटर्जी और लोकगायन (आल्हा) के लिए रामस्व पाण्डेय को सम्मानित करने

की घोषणा की गई है। वहीं लोक नृत्य के लिए सुगम सिंह शेखावत, दक्कड़ वादन के लिए मंगल प्रसाद, वायलिन वादन के लिए सुखदेव मिश्रा एवं सितार वादन के लिए वाराणसी के राजेश शाह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जबकि रंगमंच के क्षेत्र में निर्देशन के लिए सुष्मा शर्मा, अभिनय क्षेत्र में रविकांत शुक्ला ‘शिखू’, कला उन्नयन के लिए राजेश पंडित एवं कला समीक्षा के लिए शशिप्रभा तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2024 के लिए सफदर हाशमी पुरस्कार के लिए लखनऊ के शुभदीप राहा और बीएम शाह पुरस्कार के लिए भोपाल के संजय मेहता का चयन किया गया है। अध्यक्ष प्रो. जयंत ने बताया कि अकादमी की ओर से जल्द ही विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर इन सभी कलाकारों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।



लखनऊ स्थित अपने आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।

चूहामार दवा ‘रैटोल पेस्ट’ पर रोक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

फॉस्फोरस युक्त चूहानाशक घातक अवैध बिक्री रोकने के निर्देश

अमृत विचार : प्रदेश सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अवैध और अत्यंत घातक चूहानाशक उत्पाद ‘रैटोल पेस्ट’ की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जनस्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। राज्य सरकार के अनुसार, येलो या व्हाइट फॉस्फोरस युक्त यह उत्पाद (चूहामार दवा) अनुमोदित कीटनाशकों की सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में इसका निर्माण, भंडारण और बिक्री कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत दंडनीय अपराध

है। विशेषज्ञों के मुताबिक, येलो फॉस्फोरस अत्यंत विषैला और ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका कोई प्रभाव एंटीडोट उपलब्ध नहीं है और थोड़ी मात्रा में सेवन से भी गंभीर विषाक्तता या मृत्यु हो सकती है। शासन ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से ‘रैटोल पेस्ट’ या येलो फॉस्फोरस युक्त सभी उत्पादों की लिस्टिंग तत्काल हटाएं और भविष्य में इन्हें दोबारा सूचीबद्ध न होने दें। जिला कृषि रक्षा अधिकारियों और कीटनाशी निरीक्षकों को भी सघन

अभियान चलाकर करें सख्त कार्रवाई : शाही

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि चूहानाशक दवा रैटोल पेस्ट की बिक्री पर तुरंत ही प्रदेश भर में रोक लगाई जाए। यह मानव जीवन के लिए घातक है। कृषि मंत्री ने सोमवार को प्रदेश के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कृषि रक्षा अधिकारी और इंस्पेक्टर इसे लेकर सघन अभियान चलाएं और सख्त कार्रवाई करें।

निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी अवैध भंडारण या बिक्री मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृषि क्षेत्र के लिए 49.81 करोड़ रुपये स्वीकृत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

नरेंद्र देव कृषि युनिवर्सिटी परिसर में बनेगा 250 छात्रों की क्षमता का छात्रावास

किसानों को उन्नत बीज देने और मिट्टी परीक्षण के लिए भी जारी किया बजट

प्रयोगशालाओं में तैनात संविदा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन

अमृत विचार : प्रदेश की सरकार ने कृषि क्षेत्र और कृषि से संबंधित पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए खजाना खोल दिया। कृषि क्षेत्र के लिए 49.81 करोड़ किए गए मंजूर किए गए। खास बात यह है कि किसानों को अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत बीज मुहैया कराने के लिए छात्रों के लिए अयोध्या के कुमारांग स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 250 क्षमता के छात्रावास के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के अंतर्गत महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान

मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण पर खर्च की सीमा तय

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालक कल्याण कोष के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन और सेमिनार जैसे कार्यक्रमों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मत्स्य पालकों व मछुआरों के प्रशिक्षण पर कोष से व्यय की व्यवस्था को संशोधित किया गया है। मत्स्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत अब राज्यांतर्गत तथा अंतर्राज्यीय भ्रमण, क्षमता विकास, प्रदर्शन और सेमिनार कार्यक्रमों के लिए मत्स्य पालकों व मछुआरों के प्रशिक्षण और भ्रमण पर कोष की निर्धारित सीमा तक व्यय किया जा सकेगा। इससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायरा बढ़ेगा और मत्स्य पालकों को नई तकनीक और आधुनिक प्रवृत्तियों की जानकारी मिल सकेगी।

कार्यक्रम योजना में 28.78 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई। बजट में मृदा परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। प्रदेश भर की प्रत्येक तहसील पर बनी प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का निर्णय

लिया गया है। साथ ही मिट्टी की जांच के लिए 15.39 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अलावा कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा निदेशालय द्वारा कृषि आंकड़ों में सुधार करने के लिए भी धन को मंजूरी दी गई है।

जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे बॉरोइंग पावर नाबाई की आरआईडीएफ परियोजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ



मुख्य सचिव एसपी गोयल

अमृत विचार : मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाबाई की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति को सतर्कजनक बताया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की बॉरोइंग पावर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने नाबाई और कार्यदायी विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि परियोजना स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे और परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र समयबद्ध तरीके से भेजे जाएं।

प्रोजेक्ट टू बी प्रोजेक्ट यह टू बी ग्राउंडेड और स्तो मूविंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को विस्तृत विवरण नाबाई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नाबाई के मुख्य महाप्रबंधक पंकज कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में आरआईडीएफ के तहत 2419 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि 2700 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 2713 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक राज्य को 3100 करोड़ रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भाजपा के इशारे पर काम कर रहा चुनाव आयोग

अमृत विचार, लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि भाजपा फर्जी तरीके से प्रिंटेड फार्म-7 और नकली हस्ताक्षरों के जरिए सपा समर्थकों के वोट कटवाने की साजिश कर रही है। पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, लेकिन अब तक दुनियां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा प्रमुख ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होती, वहां चुनाव के दौरान डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे अधिकारियों को हटा दिया जाता है, जबकि भाजपा शासित राज्यों में ऐसा नहीं होता।



अमृत विचार

